



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 16 जुलाई, 2003/25 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 16 जुलाई, 2003

संख्या वि० स०-विधायन-बजट/1-57/2003.— हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2003 (2003

का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 16 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2003 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2003 है ।

संक्षिप्त
नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 76,48,40,61,000 रुपए (छिहत्तर अरब, अड़तालिस करोड़, चालीस लाख, इकसठ हजार रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2003-2004 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभागों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश
राज्य की
संचित निधि
में से वित्तीय
वर्ष 2003-
2004 के
लिए
76,48,40,
61,000
रुपए की
राशि जारी
करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा ।

विनियोग

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निर्ध पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा (राजस्व)	6,13,03,000	17,17,000	6,30,20,000
	(पूजी)	1,78,000	—	1,78,000
2	राज्यपाल और मंत्रि-परिषद् (राजस्व)	4,34,25,000	1,47,29,000	5,81,54,000
	(पूजी)	—	—	—
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	28,60,74,000	7,11,20,000	35,71,94,000
	और निर्वाचन (पूजी)	2,70,01,000	—	2,70,01,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	45,77,98,000	2,12,16,000	47,90,14,000
	(पूजी)	5,00,000	—	5,00,000
5	भू-राजस्व और (राजस्व)	1,43,84,99,000	—	1,43,84,99,000
	जिला प्रशासन (पूजी)	69,000	—	69,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	15,52,28,000	—	15,52,28,000
	(पूजी)	—	—	—
7	पुलिस और सम्बद्ध (राजस्व)	1,83,47,48,000	—	1,83,47,48,000
	संगठन (पूजी)	4,31,72,000	—	4,31,72,000
8	शिक्षा (राजस्व)	9,09,12,05,000	—	9,09,12,05,000
	(पूजी)	31,37,01,000	—	31,37,01,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	3,67,73,45,000	3,80,000	3,67,77,25,000
	(पूजी)	50,82,00,000	—	50,82,00,000
10	लोक निर्माण (राजस्व)	1,28,33,93,000	—	1,28,33,93,000
	भवन (पूजी)	6,57,71,000	—	6,57,71,000
11	कृषि (राजस्व)	71,76,80,000	—	71,76,80,000
	(पूजी)	38,23,00,000	—	38,23,00,000
12	उद्योग (राजस्व)	48,28,51,000	—	48,28,51,000
	(पूजी)	7,74,37,000	—	7,74,37,000
13	सिचाई और बाढ़ नियंत्रण (राजस्व)	63,69,07,000	—	63,69,07,000
	(पूजी)	1,12,31,12,000	10,00,000	1,12,41,12,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व)	67,44,64,000	—	67,44,64,000
	(पूजी)	1,86,88,000	—	1,86,88,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व)	85,37,87,000	—	85,37,87,000
	(पूजी)	15,50,83,000	—	15,50,83,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	1,50,32,64,000	—	1,50,32,64,000
	(पूजी)	1,44,77,000	—	1,44,77,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	3,11,08,85,000	—	3,11,08,85,000
	(पूँजी)	2,00,76,82,000	3,00,00,000	2,03,76,82,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खानिज (राजस्व)	22,14,83,000	4,000	22,14,87,000
	(पूँजी)	4,65,86,000	—	4,65,86,000
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित) (राजस्व)	1,13,45,52,000	—	1,13,45,52,000
	(पूँजी)	4,42,01,000	—	4,42,01,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	85,66,83,000	—	85,66,83,000
	(पूँजी)	1,11,80,000	—	1,11,80,000
21	सहकारिता (राजस्व)	11,86,38,000	—	11,86,38,000
	(पूँजी)	6,94,28,000	—	6,94,28,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	11,34,44,000	—	11,34,44,000
	(पूँजी)	53,38,000	—	53,38,000
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	61,62,56,000	—	61,62,56,000
	(पूँजी)	93,98,01,000	—	93,98,01,000
24	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व)	8,97,43,000	—	8,97,43,000
	(पूँजी)	50,000	—	50,000
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	30,56,89,000	—	30,56,89,000
	(पूँजी)	17,30,91,000	—	17,30,91,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)	3,41,06,000	—	3,41,06,000
	(पूँजी)	1,10,00,000	—	1,10,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	21,72,67,000	—	21,72,67,000
	(पूँजी)	1,80,00,000	2,00,000	1,82,00,000
28	जलापूर्ति, सफाई, ग्रावाम और नगर विकास (राजस्व)	2,39,13,63,000	—	2,39,13,63,000
	(पूँजी)	1,38,32,02,000	—	1,38,32,02,000
29	वित्त (राजस्व)	6,05,91,72,000	18,75,74,36,000	24,81,66,08,000
	(पूँजी)	11,40,01,000	8,89,94,08,000	9,01,34,09,000
30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व)	14,03,72,000	—	14,03,72,000
	(पूँजी)	1,49,01,000	—	1,49,01,000
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	1,90,99,71,000	1,13,65,000	1,92,13,36,000
	(पूँजी)	57,21,19,000	—	57,21,19,000
कुल जोड़		48,67,54,86,000	27,80,85,75,000	76,48,40,61,000
(राजस्व)		40,51,75,95,000	18,87,79,67,000	59,39,55,62,000
(पूँजी)		8,15,78,91,000	8,93,06,08,000	17,08,84,99,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

दिनांक 16 जुलाई, 2003.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन-ए0-सी0 (1)-2/2003]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2003 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किये जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2003

• वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

बीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

शिमला-171 002 :
16 जुलाई, 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year, 2003-2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2003.

Issue of a sum of Rs. 76,48,40,61,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year, 2003-2004.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 76,48,40,61,000 (Seventy six hundred forty eight crores, forty lakhs, sixty one thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year, 2003-2004 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 De- mand No.	2 Services and purposes	3		
		Sums not exceeding		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue)	6,13,03,000	17,17,000	6,30,20,000
	(Capital)	1,78,00,000	—	1,78,00,000
2	Governor and (Revenue)	4,34,25,000	1,47,29,000	5,81,54,000
	Council of Ministers (Capital)	—	—	—
3	Administration of (Revenue)	28,60,74,000	7,11,20,000	35,71,94,000
	Justice and Election (Capital)	2,70,01,000	—	2,70,01,000
4	General Adminis- (Revenue)	45,77,98,000	2,12,16,000	47,90,14,000
	tration (Capital)	5,00,000	—	5,00,000
5	Land Revenue (Revenue)	1,43,84,99,000	—	1,43,84,99,000
	and District Adminis- (Capital)	69,000	—	69,000
6	Excise and Taxation (Revenue)	15,52,28,000	—	15,52,28,000
	(Capital)	—	—	—
7	Police and Allied (Revenue)	1,83,47,48,000	—	1,83,47,48,000
	Organisations (Capital)	4,31,72,000	—	4,31,72,000
8	Education (Revenue)	9,09,12,05,000	—	9,09,12,05,000
	(Capital)	31,37,01,000	—	31,37,01,000
9	Health and Family (Revenue)	3,67,73,45,000	3,80,000	3,67,77,25,000
	Welfare (Capital)	50,82,00,000	—	50,82,00,000
10	Public Works- (Revenue)	1,28,33,93,000	—	1,28,33,93,000
	Buildings (Capital)	6,57,71,000	—	6,57,71,000
11	Agriculture (Revenue)	71,76,80,000	—	71,76,80,000
	(Capital)	38,23,00,000	—	38,23,00,000
12	Horticulture (Revenue)	48,28,51,000	—	48,28,51,000
	(Capital)	7,74,37,000	—	7,74,37,000
13	Irrigation and Flood (Revenue)	63,69,07,000	—	63,69,07,000
	Control (Capital)	1,12,31,12,000	10,00,000	1,12,41,12,000
14	Animal Husbandry (Revenue)	67,44,64,000	—	67,44,64,000
	and Diary Develop- (Capital)	1,86,88,000	—	1,86,88,000
	ment and Fisheries			
15	Planning and Back- (Revenue)	85,37,87,000	—	85,37,87,000
	ward area Sub-Plan (Capital)	15,50,83,000	—	15,50,83,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)	1,50,32,64,000	—	1,50,32,64,000
	(Capital)	1,44,77,000	—	1,44,77,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	3,11,08,85,000	—	3,11,08,85,000
	(Capital)	2,00,76,82,000	3,00,00,000	2,03,76,82,000
18	Supplies, Industries (Revenue)	22,14,83,000	4,000	22,14,87,000
	and Minerals (Capital)	4,65,86,000	—	4,65,86,000
19	Social Security and (Revenue)	1,13,45,52,000	—	1,13,45,52,000
	Welfare (including (Capital)	4,42,01,000	—	4,42,01,000
	Nutrition)			

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development (Revenue)	85,66,83,000	—	85,66,83,000
	(Capital)	1,11,80,000	—	1,11,80,000
21	Co-operation (Revenue)	11,86,38,000	—	11,86,38,000
	(Capital)	6,94,28,000	—	6,94,28,000
22	Food and Warehousing (Revenue)	11,34,44,000	—	11,34,44,000
	(Capital)	53,38,000	—	53,38,000
23	Water and Power (Revenue)	61,62,56,000	—	61,62,56,000
	(Capital)	93,98,01,000	—	93,98,01,000
24	Printing and Stationery (Revenue)	8,97,43,000	—	8,97,43,000
	(Capital)	50,000	—	50,000
25	Road and Water Transport (Revenue)	30,56,89,000	—	30,56,89,000
	(Capital)	17,30,91,000	—	17,30,91,000
26	Tourism and Civil Aviation (Revenue)	3,41,06,000	—	3,41,06,000
	(Capital)	1,10,00,000	—	1,10,00,000
27	Labour Employment (Revenue)	21,72,67,000	—	21,72,67,000
	And Training (Capital)	1,80,00,000	2,00,000	1,82,00,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development (Revenue)	2,39,13,63,000	—	2,39,13,63,000
	(Capital)	1,38,32,02,000	—	1,38,32,02,000
29	Finance (Revenue)	6,05,91,72,000	18,75,74,36,000	24,81,66,08,000
	(Capital)	11,40,01,000	8,89,94,08,000	9,01,34,09,000
30	Miscellaneous (Revenue)	14,03,72,000	—	14,03,72,000
	(Capital)	1,49,01,000	—	1,49,01,000
31	General Services (Revenue)	1,90,99,71,000	1,13,65,000	1,92,13,36,000
	(Capital)	57,21,19,000	—	57,21,19,000
Grand Total		48,67,54,86,000	27,80,85,75,000	76,48,40,61,000
(Revenue)		40,51,75,95,000	18,87,79,67,000	59,39,55,62,000
(Capital)		8,15,78,91,000	8,93,06,08,000	17,08,84,99,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year, 2003-2004.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
the 16th July, 2003.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A. C. (1) 2/2003]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 2003, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2003

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year, 2003-2004.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA-171002 :
the 16th July, 2003.